तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में एक अधिनियम बनाकर ऐसी नीति अपनाने का विचार रखती है कि वह विभिन्न राज्यों से तिलहन एकत्र करने और फिर सभी राज्यों को आवश्यकतानुसार उन्हें इनका समय पर वितरण करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रजनक बीजों के उत्पादन की व्यवस्था करती है। उसके बाद, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उन बीजों का बहुलीकरण करना राज्य सरकारों का काम है। इसके अतिरिक्त, राज्यों की आवश्यकता पूरी करने में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी केन्द्रीय बीज उत्पादक ऐजेंसियां भी बीजों का उत्पादन करती है ;

(ग) यह कहना उचित नहीं है कि बीज उपलब्ध न होने के कारण कई राज्यों में तिलहनों के उत्पादन में कमी आई है। दूसरी तरफ 1988-89 के दौरान तिलहनों का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है जो लक्ष्य स्तर से अधिक होगा।

(घ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Payment of compensation by Khanna Improvement trust

2679. SHRIMATI PRATIBHA SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Khanna Improvement Trust, Ludhiana, Punjab had acquired land in 1973 under Section 36 of the Punjab Town Improvement Act, 1922 measuring 345 Kanals and Marlas for development of residential-cum-commercial centres but the compensation has not so far been paid;

(b) what are the reasons for not paying compensation so far;

(c) whether it is also a fact that according to the Haryana Improvement Trust Act, if compensation is not paid within a period of 8 years; the scheme of acquisition of land is collapsed; and

(d) if so, whether Government shall give possession back to the owners on the ground that it has failed to pay compensation for the last 16 years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

एल्यूमिनियम की कीमत और उसके वितरण पर नियंत्रण

2680. **श्री ईश दत्त यादव : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैम्बर आफ इण्डियन ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री ने सरकार से मांग की है कि एल्यूमिनियम की कीमत और वितरण पर सरकारी नियंत्रण जारी रहना चाहिए और हिन्डाल्को-बाल्को, नाल्को, ईडाल और माल्को को अपनी-अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने की अनमति प्रदान की जाए और उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली और अन्य आवश्यक कच्चा माल सप्लाई किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र में नाल्को व बाल्को ने और प्रायवेट सैक्टर में हिन्डाल्को ने ग्रहीत बिजलीघर लगाकर अपने आपको बिजली की कमी से मुक्त

कर लिया है । प्राइवेट सैक्टर में ईन्डाल और मालको अपनी बिजली पूर्ति के लिए अभी भी राज्य बिजली बोर्डो पर निर्भर है । किन्तु ईन्डाल का भी अपने हीराकुन्ड (उड़ीसा) तथा बेलगाम (कर्नाटक) स्थित प्रद्रावकों के लिए ग्रहित बिजलीघर लगाने का प्रस्ताव है । जहां तक अन्य आवश्यक कच्चे माल जैसे बाक्साइट, फूंका हुआ पेट्रोलियम कोक, एल्यूमिनियम फलोराइट आदि का सवाल है, कोई गंभीर समस्या नहीं बताई गई है ।

एल्यूमिनियम धातु के बढ़ते हुए देशी उत्पादन से एल्यूमिनियम के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण 1 मार्च, 1989 से समाप्त कर दिया गया है 1 एल्यूमिनियम सिल्लियों और स्क्रैप का आयात पहले ही खुले सामान्य लायसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत है । मांग में किसी प्रकार की घट-बढ़ को पूरा करने की दृष्टि से एल्यूमिनियम सिल्लियों के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है और एल्यूमिनियम स्क्रैप के आयातों पर सीमा शुल्क में भारी कटौती कर दी गई है ।

Cent per cent Central assistance to National oilseed devlopment project

2681. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal of implementing National Oil Seeds Development Project (NODP) on 100 per cent Central assistance basis; and

(b) if so, the details thereof and if not ,the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) No, Sir. However, another Centrally Sponsored Scheme, Oilseeds Production Thrust Project (OPTP) has been launched since 1987-88 on 100 per cent Central assistance basis to reinforce National Oilseeds Development (NODP) Programmes.

Japanese aid for fisheries resources survey

2682. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether any Japanese aid is likely to be received for survey of fisheries resources; and

(b) if so, the details thereof including quantum of aid etc.?

THE MINITER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Government of Japan provided grant-in-aid of Japanese Yen 911 million to India pertaining to the year 1987-88 for procurment of two tuna long line fishing vessels and consultancy services. The vessels will be used by Fishery Survey of India, Bombay for survey of tuna fishery resources in India Exclusive Economic Zone.

Wage negotiations by Steel Authority of India

2683. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that wage negotiations by the Steel Authority of India Ltd., have received serious setbacks;

(b) if so, whether it has affected the production schedule of Steel Authority of India Ltd.; and

(c) by when the situation is likely to return normal?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) No, Sir. The wage negotiations are progressing satisfactorily.

(b) and (c) Do not arise.

Durgapur Steel Plant

2684. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the British-built Durgapur Steel Plant is coming